

नक्सल प्रभावित जिलों में नियुक्त होंगे युवा पेशेवर

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

नक्सल प्रभावित प्रत्येक जिले में सरकार ग्रामीण विकास की केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी निगरानी के लिए पेशेवर युवाओं को नियुक्त करेगी। तीन साल के अनुबंध पर नियुक्त होने वाले इन युवाओं को जिला मुख्यालयों पर कलेक्टरों के सहयोग के लिए रखा जाएगा। इन्हें प्रधानमंत्री के ग्रामीण विकास फेलो प्रोग्राम के तहत नियुक्त किया जाएगा।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बताया कि इस योजना को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समक्ष पिछले दिनों हुई नक्सल प्रभावित जिलों के कलेक्टरों की बैठक में रखा गया था। नक्सल प्रभावित जिलों के

- ◆ ग्रामीण योजनाओं के अमल व निगरानी में बढ़ाएंगे हाथ
- ◆ प्रभावित जिलों के कलेक्टर बैठक में शामिल



कलेक्टरों ने सरकार के इस प्रस्ताव को सराहा था। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो प्रोग्राम को अब सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय की अंतिम मुहर की दरकार है। लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद (कपाट) द्वारा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से

कार्यक्रमों का संचालन कराया जाता है। प्रधानमंत्री फेलो प्रोग्राम पर आने वाला पूरा खर्च कपाट उठाएगा। इससे खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। इसके लिए उन स्वयंसेवी संगठनों (एनजीओ) का सहयोग लिया जाएगा, जो नक्सली क्षेत्रों में पहले से ही काम कर रहे हैं। एकीकृत कार्य योजना (आइएपी) वाले सभी 60 जिलों में इनकी नियुक्ति की जाएगी। बीटक व एमबीए योग्यता वाले इन युवा पेशेवरों को 60 से 70 हजार रुपये के मासिक मानदेय के रूप में एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक इन युवाओं का मूल कार्य जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय बनाकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण योजनाओं पर अमल कराना होगा।